संख्या : 693 / IV(2)-शाठवि०-55(साठ)-2015

प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल, सचिव. उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक. शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरपालिका परिषद, बाजपुर को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत

महोदय.

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बाजपुर के पत्रांक-92/ अवस्थापना / 15—16, दिनांक 05.06.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, बाजपुर के क्षेत्रान्तर्गत 02 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराते हुए अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, बाजपुर को निम्नलिखित 02 निर्माण कार्यों हेतु टी०ए०सी० (वित्त विभाग) की संस्तुतिनुसार कुल ₹27.78 लाख (रूपये सत्ताईस लाख अठ्हत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेत् श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	(धनराशि ₹ लाख में)
1-		स्तीक्व धाराकि
163	वार्ड नं01 में रूपचन्द यादव के मकान से हीरासिंह के मकान तक टाईल्स सड़क / नाली निर्माण।	19.80
2-	वार्ड नं0 11 में द्वारिका प्रसाद से थापा एवं कुलदीप के घर तक टाईल्स सड़क, नाली निर्माण कार्य।	7.98
	योग-	27.78

उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :--2-

उक्त धनराशि कुल ₹ 27.78 लाख (रूपये सत्ताईस लाख अठ्हत्तर हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, बाजपुर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। 11.

निर्माण कार्य निर्धारित अविध के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में

पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

रवीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, III. 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति IV. प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के V. अनुरूप कराये जायेंगे।

कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप VI. से उत्तरदायी होंगे।

विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से VII.

VIII. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जायेगा, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।

IX. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा

उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

x. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

XI. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो

उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

XII. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIII. धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का

विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'20 सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता' के नामे ₹21.95 लाख, के अनुदान सं0—30 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— आयोजनागत—191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'42 अन्य व्यय के नामे ₹5.00 लाख, तथा के अनुदान सं0—31 के लेखाशीर्षक— 2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191— स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'20 सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता' के नामे ₹0.83 लाख डाला जाएगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०— 406/xxvII(2)/2015, दिनांक 26.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी—S.15.69.1.3.6.03.2..., S.15.69.3.0.0.3.3. एवं S.15.6.9.3.1.6.03.1/2 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डीoएसo गर्ब्याल) सचिव।

संख्या—⁶⁹³ (1)/IV(2)-श0वि0—2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ा. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
- आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
- 4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून। 6.

वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बाजपुर। 9.

बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

गार्ड बुक । 11.

आज्ञा र

(डी०एम०एस० राणा) उप सचिव।